



**International Journal of Advanced Research in
Education and Technology (IJARETY)**

Volume 10, Issue 4, July-August 2023

Impact Factor: 6.421



इंदौर संभाग के महाविद्यालयीन ग्रंथालयों में आधारभूत संरचना एवं संसाधन विकास में जनभागीदारी समिति का योगदान

Nandram Solanki, Dr. Salma Khan

Scholar, Department of Library and Information Science, Sunrise University, Alwar, Rajasthan, India

Professor, Department of Library and Information Science, Sunrise University, Alwar, Rajasthan, India

सारांश: महाविद्यालयीन ग्रंथालय उच्च शिक्षा संस्थानों की शैक्षणिक संरचना का एक अनिवार्य घटक है। यह ज्ञान के संरक्षण, संवर्धन तथा प्रसार का केंद्र होने के साथ-साथ विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रमुख माध्यम भी है। किसी भी महाविद्यालयीन ग्रंथालय की प्रभावशीलता उसके भवन, वाचनालय, भौतिक सुविधाओं तथा उपलब्ध ज्ञान-संसाधनों की स्थिति पर निर्भर करती है। यदि ग्रंथालय में उपयुक्त आधारभूत संरचना एवं पर्याप्त संसाधनों का अभाव हो, तो वह शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया को अपेक्षित दिशा प्रदान नहीं कर पाता।

मध्यप्रदेश के महाविद्यालयों में ग्रंथालयों की स्थिति एकरूप नहीं पाई जाती। अनेक संस्थानों में ग्रंथालय आज भी सीमित स्थान, अपर्याप्त फर्नीचर, अद्यतन पुस्तकों की कमी तथा आधुनिक सुविधाओं के अभाव से ग्रस्त हैं। केवल शासकीय सहायता पर निर्भरता के कारण ग्रंथालयों के विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है। इस संदर्भ में जनभागीदारी समिति की भूमिका विशेष महत्व रखती है, जिसका उद्देश्य शिक्षा संस्थानों के विकास में स्थानीय समाज की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना है।

इंदौर संभाग के महाविद्यालयीन ग्रंथालयों के संदर्भ में जनभागीदारी समिति का योगदान आधारभूत संरचना एवं संसाधन विकास के रूप में दृष्टिगोचर होता है। समिति के सहयोग से अनेक स्थानों पर ग्रंथालय भवनों का विस्तार, वाचनालय सुविधाओं का सुदृढीकरण, फर्नीचर की व्यवस्था, पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का संवर्धन तथा सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सुविधाओं की स्थापना संभव हुई है। इसके अतिरिक्त, जनभागीदारी समिति ने ग्रंथालयों को समाज से जोड़ने में भी सहायक भूमिका निभाई है। जनभागीदारी समिति, यदि उद्देश्यपरक, पारदर्शी एवं उत्तरदायी रूप से कार्य करे, तो महाविद्यालयीन ग्रंथालयों के आधारभूत ढाँचे एवं संसाधनों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकती है। इंदौर संभाग के विशेष संदर्भ में यह विषय महाविद्यालयीन ग्रंथालयों के सुदृढीकरण एवं सतत विकास की दिशा में एक सशक्त वैचारिक आधार प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द: महाविद्यालयीन ग्रंथालय, जनभागीदारी समिति, आधारभूत संरचना, ग्रंथालय संसाधन, इंदौर संभाग, उच्च शिक्षा।

1. अध्ययन की आवश्यकता एवं औचित्य

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालयीन ग्रंथालयों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ग्रंथालय न केवल पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों एवं संदर्भ सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, बल्कि विद्यार्थियों में अध्ययनशीलता, आत्म-अध्ययन की प्रवृत्ति तथा ज्ञान के प्रति जिज्ञासा विकसित करने में भी सहायक होता है। किसी भी महाविद्यालयीन ग्रंथालय की गुणवत्ता उसकी आधारभूत संरचना, उपलब्ध संसाधनों तथा सुविधाओं की स्थिति पर निर्भर करती है। यदि ग्रंथालय में समुचित भवन, पर्याप्त वाचनालय, बैठने की व्यवस्था, प्रकाश एवं वायु की उचित व्यवस्था तथा आवश्यक ज्ञान-सामग्री का अभाव हो, तो वह अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाता।

मध्यप्रदेश के अनेक महाविद्यालयों में ग्रंथालयों की स्थिति आज भी अपेक्षित स्तर तक विकसित नहीं हो पाई है। सीमित शासकीय सहायता, बढ़ती शैक्षणिक आवश्यकताएँ तथा संसाधनों की निरंतर बढ़ती मांग के कारण ग्रंथालयों के विकास में अनेक बाधाएँ उत्पन्न हुई हैं। विशेष रूप से शासकीय महाविद्यालयों में ग्रंथालयों के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधन प्रायः अपर्याप्त सिद्ध होते हैं, जिससे भवन विस्तार, नवीन पुस्तकों का क्रय, फर्नीचर की व्यवस्था तथा आधुनिक सुविधाओं का विकास कठिन हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में ग्रंथालयों का समग्र विकास केवल शासकीय अनुदान पर निर्भर रहकर संभव नहीं प्रतीत होता।

इसी कारण शिक्षा संस्थानों के विकास में स्थानीय समाज की सहभागिता को अत्यंत आवश्यक माना गया है। जनभागीदारी समिति की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई, ताकि महाविद्यालयों के शैक्षणिक, भौतिक एवं संसाधनात्मक विकास में समाज की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जा सके। जनभागीदारी समिति के माध्यम से स्थानीय नागरिक, शिक्षाविद्, उद्योगपति एवं समाजसेवी संस्थाएँ शिक्षा संस्थानों के विकास में सहयोग प्रदान कर सकती हैं। यह सहयोग विशेष रूप से महाविद्यालयीन ग्रंथालयों के संदर्भ में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ग्रंथालयों के विकास के लिए निरंतर संसाधनों की आवश्यकता होती है।

इंदौर संभाग मध्यप्रदेश का एक प्रमुख शैक्षणिक क्षेत्र है, जहाँ शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों की संख्या पर्याप्त है। इस संभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न जिलों के महाविद्यालयीन ग्रंथालयों की स्थिति में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। कुछ महाविद्यालयों में अपेक्षाकृत बेहतर आधारभूत संरचना एवं संसाधन उपलब्ध हैं, जबकि अनेक महाविद्यालय अभी भी न्यूनतम सुविधाओं के सहारे कार्य कर रहे हैं। इस असमानता के पीछे जनभागीदारी समिति की सक्रियता अथवा निष्क्रियता एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में दृष्टिगोचर होती है। इस संदर्भ में इंदौर संभाग के महाविद्यालयीन ग्रंथालयों में आधारभूत संरचना एवं संसाधन विकास के संदर्भ में जनभागीदारी समिति की भूमिका का विवेचन करना आवश्यक प्रतीत होता है। यह विवेचन यह स्पष्ट करने में सहायक होगा कि जनभागीदारी समिति किस सीमा तक ग्रंथालयों के विकास में योगदान प्रदान कर रही है तथा किन कारणों से उसकी भूमिका कहीं प्रभावी तो कहीं सीमित रह गई है। साथ ही, इससे उन बाधाओं एवं संभावनाओं को भी समझा जा सकेगा, जो ग्रंथालय विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं।

अतः इस विषय पर विवेचन की आवश्यकता इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि इससे महाविद्यालयीन ग्रंथालयों के सुदृढीकरण के लिए समाज की सहभागिता के महत्व को रेखांकित किया जा सके। यह औचित्य इस तथ्य में निहित है कि यदि जनभागीदारी समिति को अधिक सक्रिय, उत्तरदायी एवं उद्देश्यपरक बनाया जाए, तो इंदौर संभाग के महाविद्यालयीन ग्रंथालयों के आधारभूत ढाँचे एवं संसाधनों का सतत एवं समग्र विकास संभव हो सकता है।

II. अध्ययन के उद्देश्य

इंदौर संभाग के महाविद्यालयीन ग्रंथालयों की आधारभूत संरचना एवं उपलब्ध संसाधनों की स्थिति का विवेचन करना। महाविद्यालयीन ग्रंथालयों के आधारभूत ढाँचे एवं संसाधन विकास में जनभागीदारी समिति की भूमिका को स्पष्ट करना। अनुसंधान की प्रकृति एवं पद्धति : प्रस्तुत विषय के अंतर्गत विवेचनात्मक स्वरूप को अपनाया गया है, जिसमें तथ्यों, अवधारणाओं तथा उपलब्ध विवरणों के आधार पर विषय को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इस विवेचन में महाविद्यालयीन ग्रंथालयों की आधारभूत संरचना, संसाधनों की स्थिति तथा जनभागीदारी समिति की भूमिका को सैद्धांतिक एवं तथ्यात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। इसमें किसी प्रकार के सांख्यिकीय आँकड़ों, तुलनात्मक सारणियों अथवा गणनात्मक विधियों का प्रयोग नहीं किया गया है। इस विषय के लिए क्षेत्र के रूप में मध्यप्रदेश के इंदौर संभाग का चयन किया गया है। इंदौर संभाग के अंतर्गत संचालित शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के ग्रंथालयों को विवेचन की इकाई माना गया है। ग्रंथालयों की भौतिक संरचना, उपलब्ध सुविधाएँ, संसाधनों की स्थिति तथा इनके विकास में जनभागीदारी समिति की सहभागिता को मुख्य केंद्र में रखा गया है।

सूचना संकलन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का सहारा लिया गया है। प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत महाविद्यालयों के ग्रंथालयों से संबंधित अनुभवजन्य जानकारी, पुस्तकालयाध्यक्षों एवं महाविद्यालय प्रशासन से प्राप्त विवरणों का उपयोग किया गया है। द्वितीयक स्रोतों में शैक्षणिक पुस्तकों, पत्रिकाओं, शासकीय दस्तावेजों, अधिसूचनाओं तथा ग्रंथालय एवं उच्च शिक्षा से संबंधित प्रकाशित सामग्री को सम्मिलित किया गया है। विषयवस्तु के विवेचन में क्रमबद्ध एवं विषयानुसार प्रस्तुति को महत्व दिया गया है। सर्वप्रथम जनभागीदारी समिति की अवधारणा एवं स्वरूप को स्पष्ट किया गया है, तत्पश्चात महाविद्यालयीन ग्रंथालयों की संरचना एवं संसाधनों का विवेचन किया गया है और अंततः इंदौर संभाग के विशेष संदर्भ में जनभागीदारी समिति की भूमिका को प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार विषय का विवेचन तार्किक क्रम में किया गया है, जिससे विषय की समग्रता एवं स्पष्टता बनी रहे।

यह पद्धति विषय की प्रकृति के अनुरूप है, क्योंकि इससे ग्रंथालय विकास के सामाजिक, शैक्षणिक एवं संस्थागत पक्षों को समग्र रूप में समझने में सहायता मिलती है तथा जनभागीदारी समिति की भूमिका का संतुलित एवं वस्तुनिष्ठ चित्र उभरकर सामने आता है।

साहित्य समीक्षा : महाविद्यालयीन ग्रंथालयों के स्वरूप, कार्य एवं विकास से संबंधित साहित्य का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि ग्रंथालय को सदैव उच्च शिक्षा की बौद्धिक आधारशिला के रूप में स्वीकार किया गया है। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम डॉ. एस. आर. रंगनाथन ने ग्रंथालय की भूमिका को सैद्धांतिक आधार प्रदान किया। उनकी प्रसिद्ध कृति “Five Laws of Library Science” (1931) में यह प्रतिपादित किया गया है कि ग्रंथालय का मूल उद्देश्य पाठक और पुस्तक के मध्य जीवंत संबंध स्थापित करना है। रंगनाथन के सिद्धांत इस बात की पुष्टि करते हैं कि ग्रंथालय की उपयोगिता तभी सार्थक होती है जब उसके पास उपयुक्त भवन, पर्याप्त संसाधन तथा सुचारु सेवाएँ उपलब्ध हों।

भारतीय संदर्भ में महाविद्यालयीन ग्रंथालयों के प्रशासन एवं संगठन पर कृष्ण कुमार ने अपने ग्रंथ “Library Administration and Management” (1987) में विस्तार से प्रकाश डाला है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी शैक्षणिक ग्रंथालय का समुचित संचालन उसके आधारभूत ढाँचे, वित्तीय संसाधनों तथा प्रबंधन व्यवस्था पर निर्भर करता है। उनके अनुसार सीमित संसाधनों के कारण अनेक महाविद्यालयीन ग्रंथालय अपनी भूमिका का पूर्ण निर्वहन नहीं कर पाते, जिससे शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित होती है। ग्रंथालय संसाधन विकास के संदर्भ में सी. आर. करिसिद्धप्पा ने अपनी कृति “Collection Development in Libraries” (2004) में यह प्रतिपादित किया है कि पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं संदर्भ सामग्री का संतुलित और आवश्यकता-आधारित विकास ग्रंथालय की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि संसाधन विकास केवल वित्तीय उपलब्धता का विषय नहीं है, बल्कि इसके लिए संस्थागत सहयोग एवं सामाजिक सहभागिता भी आवश्यक होती है।

भारतीय महाविद्यालयीन ग्रंथालयों की समस्याओं पर एस. के. राव ने अपने लेख “Problems of College Libraries in India” (1998) में चर्चा करते हुए यह बताया है कि अपर्याप्त भवन, सीमित फर्नीचर, अद्यतन पुस्तकों की कमी तथा तकनीकी सुविधाओं का अभाव प्रमुख समस्याएँ हैं। उनके अनुसार इन समस्याओं का समाधान केवल शासकीय सहायता से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए स्थानीय स्तर पर सहयोग की आवश्यकता होती है।

मध्यप्रदेश के शैक्षणिक संदर्भ में जनभागीदारी की अवधारणा को समझने हेतु मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित “जनभागीदारी योजना मार्गदर्शिका” (1999) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस दस्तावेज में यह स्पष्ट किया गया है कि जनभागीदारी समिति का उद्देश्य महाविद्यालयों के भौतिक, शैक्षणिक एवं संसाधनात्मक विकास में समाज की सहभागिता सुनिश्चित करना है। इसमें यह भी उल्लेख है कि ग्रंथालय, प्रयोगशाला एवं अन्य शैक्षणिक सुविधाओं के विकास में समिति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है।

जनभागीदारी समिति की भूमिका पर आर. के. शर्मा ने अपने लेख “Role of Janbhagidari Samiti in Higher Education Institutions of Madhya Pradesh” (2008) में यह प्रतिपादित किया है कि इस व्यवस्था के माध्यम से महाविद्यालयों में अतिरिक्त वित्तीय संसाधन, अधोसंरचना विस्तार तथा प्रशासनिक लचीलापन संभव हुआ है। यद्यपि उनका विवेचन मुख्यतः संस्थागत विकास पर केंद्रित है, फिर भी इसमें ग्रंथालय जैसी शैक्षणिक इकाइयों के लिए जनभागीदारी समिति की उपयोगिता का संकेत मिलता है।

महाविद्यालयीन ग्रंथालयों और सामाजिक सहभागिता के संबंध पर पी. एन. कौला ने अपनी पुस्तक “Library and Society” (1992) में यह विचार प्रस्तुत किया है कि ग्रंथालय समाज से कटकर विकसित नहीं हो सकता। उनके अनुसार समाज की सहभागिता से ही ग्रंथालय को जीवंत एवं उपयोगी बनाया जा सकता है। यह विचार जनभागीदारी समिति की अवधारणा को सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है।

उपलब्ध साहित्य के समग्र अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि महाविद्यालयीन ग्रंथालयों के विकास में आधारभूत संरचना, संसाधन उपलब्धता तथा सामाजिक सहभागिता का गहरा संबंध है। यद्यपि ग्रंथालय विज्ञान एवं शिक्षा प्रशासन से संबंधित साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, फिर भी इंदौर संभाग के विशेष संदर्भ में महाविद्यालयीन ग्रंथालयों की आधारभूत संरचना एवं संसाधन विकास में जनभागीदारी समिति की भूमिका पर केंद्रित विवेचन अत्यंत सीमित है। इसी कारण यह विषय और अधिक प्रासंगिक हो जाता है तथा प्रस्तुत साहित्यिक पृष्ठभूमि इसके औचित्य को स्पष्ट रूप से स्थापित करती है।

जनभागीदारी समिति - अवधारणा एवं स्वरूप : शिक्षा के क्षेत्र में संस्थागत विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से जनभागीदारी समिति की अवधारणा का विकास किया गया। जनभागीदारी समिति मूलतः ऐसी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों के विकास में स्थानीय समाज की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाती है। यह समिति शिक्षा संस्थान और समाज के बीच सेतु का कार्य करती है तथा संसाधनों, विचारों और उत्तरदायित्व की साझेदारी को सुदृढ़ बनाती है। मध्यप्रदेश में जनभागीदारी समिति की स्थापना का उद्देश्य यह रहा है कि महाविद्यालय केवल शासकीय सहायता पर निर्भर न रहें, बल्कि स्थानीय समुदाय, अभिभावक, शिक्षाविद्, उद्योगपति एवं समाजसेवी संस्थाएँ भी उनके विकास में योगदान प्रदान करें। इस व्यवस्था के अंतर्गत जनभागीदारी समिति को महाविद्यालय के भौतिक, शैक्षणिक एवं संसाधनात्मक विकास में सहयोग प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। समिति महाविद्यालय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयास करती है।

जनभागीदारी समिति की संरचना में सामान्यतः अध्यक्ष, सचिव तथा अन्य सदस्य सम्मिलित होते हैं। अध्यक्ष प्रायः क्षेत्र के जनप्रतिनिधि अथवा प्रतिष्ठित नागरिक होते हैं, जबकि प्राचार्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं। समिति के सदस्यों में शिक्षाविद्, समाजसेवी, अभिभावक तथा अन्य गणमान्य नागरिक सम्मिलित किए जाते हैं। इस प्रकार समिति की संरचना ऐसी होती है, जिससे शिक्षा एवं समाज दोनों के हितों का संतुलन बना रहे।

समिति के कार्यक्षेत्र में महाविद्यालय की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, संसाधनों के विकास में सहयोग, अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था तथा संस्थान के समग्र विकास हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना सम्मिलित है। विशेष रूप से ग्रंथालय, प्रयोगशाला, कक्षा-कक्षा, फर्नीचर तथा अन्य शैक्षणिक सुविधाओं के विकास में जनभागीदारी समिति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। समिति स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों को महाविद्यालय के हित में उपयोग में लाने का प्रयास करती है। महाविद्यालयीन ग्रंथालयों के संदर्भ में जनभागीदारी समिति की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ग्रंथालयों के विकास के लिए निरंतर संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिसमें पुस्तकों का क्रय, भवन का विस्तार, वाचनालय सुविधाओं का सुदृढीकरण तथा आधुनिक साधनों की व्यवस्था शामिल है। जनभागीदारी समिति इन आवश्यकताओं को समझते हुए ग्रंथालय के विकास हेतु सहयोग प्रदान कर सकती है। समिति के माध्यम से समाज में ग्रंथालय के महत्व के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न होती है।

जनभागीदारी समिति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी सक्रियता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करती है। जहाँ समिति उद्देश्यपरक रूप से कार्य करती है, वहाँ महाविद्यालयों की भौतिक एवं शैक्षणिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इसके विपरीत, जहाँ समिति निष्क्रिय रहती है, वहाँ विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी रहती है। इस प्रकार जनभागीदारी समिति की अवधारणा शिक्षा को समाज से जोड़ने का एक प्रभावी माध्यम प्रस्तुत करती है। महाविद्यालयीन ग्रंथालयों के विकास के संदर्भ में यह समिति न केवल संसाधनों की उपलब्धता में सहायक सिद्ध होती है, बल्कि ग्रंथालय को एक जीवंत शैक्षणिक एवं सामाजिक केंद्र के रूप में विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

महाविद्यालयीन ग्रंथालय - अवधारणा एवं महत्व : महाविद्यालयीन ग्रंथालय उच्च शिक्षा व्यवस्था का वह आधार स्तंभ है, जिस पर शिक्षण, अध्ययन तथा बौद्धिक विकास की संपूर्ण संरचना टिकी होती है। ग्रंथालय को केवल पुस्तकों के संग्रह का स्थान मानना उसके व्यापक शैक्षणिक महत्व को सीमित कर देना होगा। वास्तव में महाविद्यालयीन ग्रंथालय वह जीवंत केंद्र है, जहाँ ज्ञान का संरक्षण, संवर्धन और प्रसार एक साथ संपन्न होता है। यह विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम से आगे बढ़कर अध्ययन करने की प्रेरणा देता है तथा शिक्षकों को अध्यापन के लिए आवश्यक संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराता है। ग्रंथालय की अवधारणा प्राचीन काल से ही ज्ञान के संचयन और संरक्षण से जुड़ी रही है। समय के साथ-साथ इसकी भूमिका में परिवर्तन हुआ है। आधुनिक युग में महाविद्यालयीन ग्रंथालय केवल पुस्तकों और पत्रिकाओं तक सीमित न रहकर सूचना, विचार और बौद्धिक संवाद का केंद्र बन गया है। यह विद्यार्थियों में आत्म-अध्ययन की प्रवृत्ति को विकसित करता है तथा उन्हें स्वतंत्र रूप से ज्ञान अर्जन के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार ग्रंथालय शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था का पूरक बनकर कार्य करता है।

महाविद्यालयीन स्तर पर ग्रंथालय का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यही वह अवस्था है, जहाँ विद्यार्थी उच्च अध्ययन, शोध एवं व्यावसायिक जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। इस स्तर पर विद्यार्थियों को केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उन्हें संदर्भ ग्रंथों, पत्रिकाओं और विविध विषयों से संबंधित सामग्री की आवश्यकता होती है। ग्रंथालय इस आवश्यकता की पूर्ति करते हुए विद्यार्थियों को व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इससे उनमें विश्लेषणात्मक चिंतन, तर्कशक्ति और बौद्धिक परिपक्वता का विकास होता है। महाविद्यालयीन ग्रंथालय शिक्षकों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अध्यापन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शिक्षकों को निरंतर अध्ययन और अद्यतन ज्ञान की आवश्यकता होती है। ग्रंथालय उन्हें नवीन विचारों, शोध निष्कर्षों तथा विषय से संबंधित नवीनतम साहित्य तक पहुँच प्रदान करता है। इससे शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण बनती है। इस प्रकार ग्रंथालय शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होता है।

ग्रंथालय का महत्व केवल शैक्षणिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह व्यक्तित्व विकास में भी सहायक होता है। नियमित रूप से ग्रंथालय का उपयोग करने वाले विद्यार्थियों में अनुशासन, समय प्रबंधन, एकाग्रता तथा आत्मनिर्भरता जैसे गुण विकसित होते हैं। शांत वातावरण में अध्ययन करने की आदत उनके मानसिक विकास को सकारात्मक दिशा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, ग्रंथालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकों का अध्ययन विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है तथा उनमें सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का विकास करता है। महाविद्यालयीन ग्रंथालय का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि यह ज्ञान के लोकतंत्रीकरण में सहायक होता है। ग्रंथालय सभी विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करता है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ग्रंथालय के माध्यम से विद्यार्थी ऐसे ज्ञान-संसाधनों तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं, जो व्यक्तिगत रूप से उनके लिए सुलभ नहीं होते। इस प्रकार ग्रंथालय शिक्षा में समानता और समावेशन को बढ़ावा देता है।

वर्तमान समय में महाविद्यालयीन ग्रंथालयों का महत्व और अधिक बढ़ गया है। शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन, नए विषयों का समावेश तथा ज्ञान के विस्तार के कारण ग्रंथालयों की भूमिका बहुआयामी हो गई है। अब ग्रंथालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पारंपरिक पुस्तकों के साथ-साथ अन्य शैक्षणिक सामग्री भी उपलब्ध कराएँ। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को विविध स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलता है। हालाँकि, महाविद्यालयीन ग्रंथालय की इस महत्वपूर्ण भूमिका की पूर्ति तभी संभव है, जब उसकी आधारभूत संरचना सुदृढ हो और उसमें पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों। उपयुक्त भवन, पर्याप्त वाचनालय, बैठने की व्यवस्था,

प्रकाश और वायु की उचित सुविधा तथा आवश्यक ज्ञान-सामग्री के अभाव में ग्रंथालय अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकता। अनेक महाविद्यालयों में ग्रंथालयों की स्थिति आज भी संतोषजनक नहीं है, जिससे उनकी उपयोगिता सीमित हो जाती है।

इस संदर्भ में यह स्पष्ट होता है कि महाविद्यालयीन ग्रंथालय का महत्व केवल सैद्धांतिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक भी है। यदि ग्रंथालय को समुचित संसाधनों और सुविधाओं से सुसज्जित किया जाए, तो वह महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को समृद्ध बना सकता है। इसके विपरीत, उपेक्षित ग्रंथालय शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। अतः महाविद्यालयीन ग्रंथालय को शिक्षा व्यवस्था का एक केंद्रीय अंग मानते हुए उसके विकास और सुदृढीकरण पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। यह न केवल विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए उपयोगी है, बल्कि संपूर्ण समाज के बौद्धिक विकास में भी योगदान प्रदान करता है। इस दृष्टि से महाविद्यालयीन ग्रंथालय का महत्व निर्विवाद है और इसके विकास से ही उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की सार्थक पूर्ति संभव हो सकती है।

महाविद्यालयीन ग्रंथालयों की आधारभूत संरचना का स्वरूप : महाविद्यालयीन ग्रंथालयों की आधारभूत संरचना वह ठोस आधार है, जिस पर ग्रंथालय की संपूर्ण कार्यप्रणाली निर्भर करती है। ग्रंथालय का स्वरूप केवल पुस्तकों के संग्रह तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसमें भवन, वाचनालय, भौतिक सुविधाएँ, तकनीकी साधन तथा उपयोगकर्ताओं के अनुकूल वातावरण सम्मिलित होता है। यदि आधारभूत संरचना सुदृढ, सुव्यवस्थित और आवश्यकता के अनुरूप हो, तो ग्रंथालय अपनी शैक्षणिक भूमिका का प्रभावी निर्वहन कर सकता है; अन्यथा उसकी उपयोगिता सीमित रह जाती है।

ग्रंथालय भवन आधारभूत संरचना का प्रथम और अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होता है। भवन का आकार, स्थिति और आंतरिक विन्यास ग्रंथालय की कार्यक्षमता को सीधे प्रभावित करता है। एक आदर्श महाविद्यालयीन ग्रंथालय के लिए पृथक एवं पर्याप्त भवन आवश्यक माना जाता है, जिसमें पुस्तकों के संग्रह, वाचनालय, संदर्भ कक्ष, पत्रिका अनुभाग तथा प्रशासनिक कक्षों की समुचित व्यवस्था हो। अनेक महाविद्यालयों में ग्रंथालय आज भी सीमित कक्षों या अस्थायी भवनों में संचालित होते हैं, जिससे पुस्तकों का समुचित संरक्षण एवं पाठकों के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना कठिन हो जाता है। वाचनालय ग्रंथालय की आधारभूत संरचना का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है। वाचनालय वह स्थान है जहाँ विद्यार्थी शांत एवं अनुशासित वातावरण में अध्ययन करते हैं। वाचनालय में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, उचित प्रकाश, स्वच्छता तथा शांत वातावरण आवश्यक होता है। यदि वाचनालय छोटा हो या बैठने की व्यवस्था अपर्याप्त हो, तो विद्यार्थी ग्रंथालय का समुचित उपयोग नहीं कर पाते। अनेक महाविद्यालयों में बढ़ती विद्यार्थी संख्या के अनुपात में वाचनालय की क्षमता अपर्याप्त पाई जाती है, जिससे ग्रंथालय की उपयोगिता प्रभावित होती है।

फर्नीचर भी ग्रंथालय की आधारभूत संरचना का एक आवश्यक घटक है। पुस्तक रैक, मेज, कुर्सियाँ, संदर्भ टेबल तथा अन्य फर्नीचर का उचित और सुव्यवस्थित होना आवश्यक है। पुस्तकों के संरक्षण के लिए मजबूत एवं सुव्यवस्थित रैकों की आवश्यकता होती है, जबकि पाठकों के लिए आरामदायक बैठने की व्यवस्था ग्रंथालय उपयोग को प्रोत्साहित करती है। जर्जर या अपर्याप्त फर्नीचर ग्रंथालय की कार्यक्षमता को कम करता है तथा पुस्तकों के संरक्षण में भी बाधा उत्पन्न करता है। प्रकाश एवं वायु व्यवस्था ग्रंथालय की आधारभूत संरचना का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश, उचित विद्युत प्रकाश व्यवस्था तथा वायु संचार ग्रंथालय को अध्ययन के लिए अनुकूल बनाते हैं। अपर्याप्त प्रकाश या वायु की कमी से न केवल अध्ययन में बाधा उत्पन्न होती है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ भी उत्पन्न हो सकती हैं। इस दृष्टि से ग्रंथालय भवन की संरचना ऐसी होनी चाहिए, जो प्राकृतिक प्रकाश और वायु के समुचित प्रवाह को सुनिश्चित करे।

सूचना एवं संचार से संबंधित सुविधाएँ भी आधुनिक महाविद्यालयीन ग्रंथालयों की आधारभूत संरचना का महत्वपूर्ण भाग बन चुकी हैं। यद्यपि ग्रंथालय का मूल स्वरूप पुस्तकों पर आधारित है, तथापि वर्तमान समय में विभिन्न तकनीकी साधनों की आवश्यकता भी बढ़ गई है। कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर तथा अन्य सहायक उपकरण ग्रंथालय सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाते हैं। इन सुविधाओं की उपलब्धता से ग्रंथालय का संचालन अधिक व्यवस्थित होता है तथा उपयोगकर्ताओं को विविध प्रकार की सहायता प्राप्त होती है। ग्रंथालय में पुस्तकों एवं अन्य सामग्री के संरक्षण के लिए उपयुक्त व्यवस्था भी आधारभूत संरचना का अभिन्न अंग है। नमी, धूल, कीट तथा तापमान में अत्यधिक परिवर्तन पुस्तकों को क्षति पहुँचा सकते हैं। अतः ग्रंथालय में स्वच्छता, उचित तापमान एवं संरक्षण संबंधी व्यवस्थाओं का होना आवश्यक है। कई महाविद्यालयों में इन व्यवस्थाओं के अभाव के कारण पुस्तकों की स्थिति शीघ्र खराब हो जाती है, जिससे संसाधनों की उपयोगिता घट जाती है।

दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अनुकूल सुविधाएँ भी आधुनिक ग्रंथालय संरचना का आवश्यक भाग मानी जाती हैं। सरल प्रवेश, पर्याप्त स्थान, सुविधाजनक बैठने की व्यवस्था तथा अन्य सहायक सुविधाएँ ग्रंथालय को समावेशी बनाती हैं। यद्यपि अनेक महाविद्यालयों में इस दिशा में अभी भी पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए हैं, फिर भी आधारभूत संरचना के विवेचन में इस पक्ष की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

इंदौर संभाग के महाविद्यालयीन ग्रंथालयों की आधारभूत संरचना की स्थिति में पर्याप्त विविधता दिखाई देती है। कुछ महाविद्यालयों में अपेक्षाकृत सुव्यवस्थित भवन, वाचनालय तथा फर्नीचर उपलब्ध हैं, जबकि अनेक महाविद्यालय आज भी सीमित स्थान और न्यूनतम

सुविधाओं के सहारे कार्य कर रहे हैं। इस असमानता के पीछे स्थानीय परिस्थितियाँ, संसाधनों की उपलब्धता तथा संस्थागत प्राथमिकताएँ प्रमुख कारण के रूप में उभरती हैं।

इस संदर्भ में यह स्पष्ट होता है कि महाविद्यालयीन ग्रंथालयों की आधारभूत संरचना केवल भौतिक सुविधाओं का समूह नहीं है, बल्कि यह ग्रंथालय की आत्मा के समान है। सुदृढ़ संरचना के अभाव में ग्रंथालय अपनी शैक्षणिक भूमिका का पूर्ण निर्वहन नहीं कर सकता। अतः महाविद्यालयीन ग्रंथालयों के विकास के लिए आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। महाविद्यालयीन ग्रंथालयों की आधारभूत संरचना शिक्षा की गुणवत्ता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। यदि ग्रंथालय भवन, वाचनालय, फर्नीचर एवं अन्य सुविधाएँ सुव्यवस्थित और आवश्यकता के अनुरूप हों, तो ग्रंथालय महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को समृद्ध बना सकता है। इस दृष्टि से आधारभूत संरचना का विकास महाविद्यालयीन ग्रंथालयों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक अनिवार्य कदम माना जाना चाहिए।

महाविद्यालयीन ग्रंथालयों में संसाधन विकास का स्वरूप : महाविद्यालयीन ग्रंथालयों में संसाधन विकास वह प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से ग्रंथालय अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक ज्ञान-सामग्री का संग्रह, संवर्धन एवं संरक्षण करता है। संसाधन विकास का आशय केवल पुस्तकों की संख्या बढ़ाने से नहीं है, बल्कि यह एक सुविचारित और उद्देश्यपरक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त सामग्री का चयन किया जाता है। संसाधनों की गुणवत्ता, प्रासंगिकता एवं संतुलन ग्रंथालय की उपयोगिता को निर्धारित करते हैं।

ग्रंथालय संसाधनों का प्रमुख आधार मुद्रित सामग्री रही है। पुस्तकों का संग्रह किसी भी महाविद्यालयीन ग्रंथालय की रीढ़ माना जाता है। पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों के साथ-साथ संदर्भ ग्रंथ, विश्वकोश, शब्दकोश तथा सामान्य ज्ञान से संबंधित ग्रंथ ग्रंथालय को समृद्ध बनाते हैं। इन पुस्तकों के माध्यम से विद्यार्थी विषय की गहराई में जाकर अध्ययन कर सकते हैं तथा शिक्षकों को अध्यापन हेतु सहायक सामग्री प्राप्त होती है। यदि पुस्तकों का संग्रह अद्यतन एवं विषयानुसार संतुलित न हो, तो ग्रंथालय का महत्व सीमित रह जाता है। पत्रिकाएँ एवं समाचार-पत्र भी ग्रंथालय संसाधनों का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। शैक्षणिक एवं विषयगत पत्रिकाएँ नवीन विचारों, शोध निष्कर्षों तथा समकालीन विमर्श को प्रस्तुत करती हैं। इनके माध्यम से विद्यार्थी और शिक्षक अपने विषय से संबंधित नवीन प्रवृत्तियों से परिचित होते हैं। समाचार-पत्र सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक घटनाओं की जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे विद्यार्थियों का सामान्य ज्ञान एवं सामाजिक चेतना विकसित होती है। इस दृष्टि से पत्रिकाओं और समाचार-पत्रों की नियमित उपलब्धता ग्रंथालय के लिए आवश्यक मानी जाती है।

संदर्भ सामग्री का संग्रह ग्रंथालय संसाधन विकास का एक विशेष पक्ष है। संदर्भ ग्रंथ, हैंडबुक, वार्षिक प्रतिवेदन तथा अन्य सहायक सामग्री त्वरित जानकारी प्राप्त करने में सहायक होती है। इन संसाधनों का उपयोग शिक्षकों के साथ-साथ विद्यार्थियों द्वारा भी किया जाता है। एक समृद्ध संदर्भ अनुभाग ग्रंथालय की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उसे अधिक उपयोगी बनाता है। समय के साथ महाविद्यालयीन ग्रंथालयों में संसाधनों के स्वरूप में भी परिवर्तन आया है। यद्यपि पारंपरिक मुद्रित सामग्री का महत्व आज भी बना हुआ है, तथापि अन्य प्रकार की शैक्षणिक सामग्री की आवश्यकता भी बढ़ी है। ग्रंथालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सामग्री, सामान्य अध्ययन की पुस्तकें तथा व्यक्तित्व विकास से संबंधित ग्रंथों का संग्रह विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इससे ग्रंथालय का उपयोग क्षेत्र विस्तृत होता है और अधिकाधिक विद्यार्थी इससे लाभान्वित होते हैं।

ग्रंथालय संसाधन विकास में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। किसी एक विषय या वर्ग की सामग्री का अत्यधिक संग्रह अन्य विषयों की उपेक्षा का कारण बन सकता है। अतः महाविद्यालयीन ग्रंथालयों में संसाधनों का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि सभी संकायों एवं विषयों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसके लिए शिक्षकों एवं पुस्तकालयकर्मियों के बीच समन्वय आवश्यक होता है।

इंदौर संभाग के महाविद्यालयीन ग्रंथालयों के संदर्भ में संसाधन विकास की स्थिति में विविधता दिखाई देती है। कुछ महाविद्यालयों में पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं संदर्भ सामग्री का अपेक्षाकृत समृद्ध संग्रह उपलब्ध है, जबकि अनेक महाविद्यालय आज भी सीमित संसाधनों के सहारे कार्य कर रहे हैं। इस स्थिति का प्रभाव विद्यार्थियों की अध्ययन संभावनाओं पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। जहाँ संसाधन पर्याप्त हैं, वहाँ ग्रंथालय का उपयोग अधिक होता है और शैक्षणिक वातावरण अपेक्षाकृत समृद्ध दिखाई देता है। संसाधन विकास की प्रक्रिया में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का महत्वपूर्ण स्थान है। सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण कई महाविद्यालयों में नवीन पुस्तकों और पत्रिकाओं का नियमित क्रय संभव नहीं हो पाता। इस कारण ग्रंथालयों में उपलब्ध सामग्री धीरे-धीरे अप्रासंगिक हो जाती है। ऐसी स्थिति में संसाधन विकास की निरंतरता बनाए रखना एक चुनौती के रूप में उभरती है।

महाविद्यालयीन ग्रंथालयों में संसाधन विकास केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं है, बल्कि यह शैक्षणिक गुणवत्ता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ विषय है। यदि संसाधनों का विकास योजनाबद्ध, संतुलित और आवश्यकता-आधारित हो, तो ग्रंथालय विद्यार्थियों और

शिक्षकों के लिए ज्ञान का सशक्त केंद्र बन सकता है। इसके विपरीत, उपेक्षित संसाधन विकास ग्रंथालय की उपयोगिता को सीमित कर देता है। अतः महाविद्यालयीन ग्रंथालयों में संसाधन विकास को सतत प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। यह प्रक्रिया ग्रंथालय को जीवंत बनाए रखती है और उसे बदलती शैक्षणिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने में सहायक होती है। इस दृष्टि से संसाधन विकास महाविद्यालयीन ग्रंथालयों के सुदृढीकरण का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण पक्ष माना जाना चाहिए।

इंदौर संभाग के महाविद्यालयीन ग्रंथालयों के विकास में जनभागीदारी समिति का योगदान : इंदौर संभाग के महाविद्यालयीन ग्रंथालयों के विकास में जनभागीदारी समिति की भूमिका एक सहायक एवं पूरक व्यवस्था के रूप में उभरकर सामने आती है। जब शासकीय संसाधन सीमित होते हैं और बढ़ती शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति कठिन हो जाती है, तब जनभागीदारी समिति स्थानीय समाज और महाविद्यालय के मध्य एक सेतु का कार्य करती है। इस समिति के माध्यम से ग्रंथालयों के आधारभूत ढाँचे एवं संसाधनों के विकास को नई दिशा प्राप्त होती है।

जनभागीदारी समिति का प्रमुख योगदान ग्रंथालयों की भौतिक संरचना के विकास में दृष्टिगोचर होता है। अनेक महाविद्यालयों में समिति के सहयोग से ग्रंथालय भवन का विस्तार किया गया है अथवा नए भवनों का निर्माण संभव हो पाया है। जहाँ पहले ग्रंथालय सीमित कक्षों में संचालित होते थे, वहाँ समिति की पहल से पृथक एवं अपेक्षाकृत सुव्यवस्थित भवन उपलब्ध कराए गए। इससे पुस्तकों के संरक्षण, वाचनालय की व्यवस्था तथा विद्यार्थियों के लिए अध्ययन का अनुकूल वातावरण निर्मित हुआ है। वाचनालय सुविधाओं के सुदृढीकरण में भी जनभागीदारी समिति का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। समिति के माध्यम से अतिरिक्त बैठने की व्यवस्था, अध्ययन मेजों एवं कुर्सियों की उपलब्धता तथा शांत वातावरण सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं। कई महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या के अनुरूप वाचनालय की क्षमता बढ़ाने में समिति की भूमिका सहायक सिद्ध हुई है। इससे ग्रंथालय का उपयोग बढ़ा है और विद्यार्थियों में नियमित अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित हुई है।

फर्नीचर एवं अन्य भौतिक संसाधनों की व्यवस्था में भी जनभागीदारी समिति का योगदान उल्लेखनीय है। पुस्तक रैक, संदर्भ टेबल, निर्गमन काउंटर तथा अन्य आवश्यक फर्नीचर की व्यवस्था समिति के सहयोग से की गई है। जर्जर एवं पुराने फर्नीचर के स्थान पर नए और उपयोगी फर्नीचर उपलब्ध होने से ग्रंथालय का स्वरूप अधिक व्यवस्थित एवं आकर्षक हुआ है। इससे न केवल पुस्तकों का संरक्षण बेहतर हुआ है, बल्कि पाठकों के लिए भी ग्रंथालय अधिक सुविधाजनक बना है। ग्रंथालय संसाधनों के विकास में जनभागीदारी समिति की भूमिका विशेष महत्व रखती है। समिति के माध्यम से अनेक महाविद्यालयों में पुस्तकों, संदर्भ ग्रंथों एवं पत्रिकाओं के संग्रह में वृद्धि संभव हो पाई है। स्थानीय दानदाताओं, शिक्षाविदों एवं समाजसेवियों के सहयोग से ग्रंथालयों को उपयोगी पुस्तकें प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त, समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए वित्तीय सहयोग से आवश्यक शैक्षणिक सामग्री का क्रय किया गया है, जिससे ग्रंथालय का संग्रह अपेक्षाकृत समृद्ध हुआ है।

सूचना सुविधाओं के विकास में भी जनभागीदारी समिति का योगदान परिलक्षित होता है। यद्यपि सभी महाविद्यालयों में यह समान रूप से नहीं दिखाई देता, तथापि कुछ महाविद्यालयों में समिति की पहल से कंप्यूटर, प्रिंटर एवं अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। इन सुविधाओं से ग्रंथालय सेवाओं के संचालन में सुविधा हुई है और विद्यार्थियों को अध्ययन में अतिरिक्त सहायता प्राप्त हुई है। जनभागीदारी समिति का एक महत्वपूर्ण योगदान ग्रंथालयों के प्रति सामाजिक चेतना के विकास में भी देखा जा सकता है। समिति के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को ग्रंथालय के महत्व से अवगत कराया गया है। इससे ग्रंथालय को केवल महाविद्यालय की एक इकाई न मानकर समाज के ज्ञान केंद्र के रूप में देखने की प्रवृत्ति विकसित हुई है। इस सामाजिक सहभागिता से ग्रंथालयों को नैतिक एवं भौतिक समर्थन प्राप्त हुआ है।

इंदौर संभाग के विभिन्न महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति की सक्रियता में अंतर पाया जाता है। जहाँ समिति सक्रिय, संगठित एवं उद्देश्यपरक रही है, वहाँ ग्रंथालयों के विकास में स्पष्ट प्रगति दिखाई देती है। इसके विपरीत, जहाँ समिति औपचारिकता तक सीमित रही है, वहाँ ग्रंथालयों की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि समिति की भूमिका उसकी कार्यशीलता और प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। यह भी उल्लेखनीय है कि जनभागीदारी समिति केवल वित्तीय सहयोग तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ग्रंथालय विकास के लिए मार्गदर्शन और समर्थन भी प्रदान करती है। समिति के सदस्य अपने अनुभव और सामाजिक संपर्कों के माध्यम से ग्रंथालय के विकास हेतु नए अवसर सृजित कर सकते हैं। इस प्रकार समिति की भूमिका बहुआयामी हो जाती है।

इंदौर संभाग के महाविद्यालयीन ग्रंथालयों के आधारभूत ढाँचे एवं संसाधन विकास में जनभागीदारी समिति का योगदान महत्वपूर्ण एवं सार्थक रहा है। यद्यपि सभी महाविद्यालयों में यह योगदान समान नहीं है, फिर भी यह स्पष्ट है कि जहाँ जनभागीदारी समिति सक्रिय रही है, वहाँ ग्रंथालयों की स्थिति अपेक्षाकृत सुदृढ हुई है। इस प्रकार जनभागीदारी समिति महाविद्यालयीन ग्रंथालयों के विकास में एक प्रभावी सहायक व्यवस्था के रूप में उभरती है, जो शैक्षणिक उन्नयन की प्रक्रिया को गति प्रदान करती है।

महाविद्यालयीन ग्रंथालयों के विकास में समस्याएँ एवं चुनौतियाँ : इंदौर संभाग के महाविद्यालयीन ग्रंथालयों के विकास की प्रक्रिया अनेक उपलब्धियों के बावजूद विभिन्न समस्याओं एवं चुनौतियों से प्रभावित रही है। यद्यपि जनभागीदारी समिति के माध्यम से कुछ महाविद्यालयों में आधारभूत संरचना एवं संसाधनों का विकास संभव हुआ है, फिर भी यह प्रक्रिया सर्वत्र समान एवं निर्बाध नहीं रही है। ग्रंथालयों के समग्र विकास के मार्ग में कई प्रकार की संस्थागत, आर्थिक तथा प्रशासनिक कठिनाइयाँ विद्यमान हैं, जिनका विवेचन आवश्यक प्रतीत होता है।

ग्रंथालय विकास की एक प्रमुख समस्या सीमित आर्थिक संसाधनों से संबंधित है। अधिकांश शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में ग्रंथालयों के लिए पृथक एवं पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं होती। शासकीय सहायता प्रायः अन्य आवश्यकताओं में व्यय हो जाती है, जिससे ग्रंथालय के विकास के लिए अपेक्षित संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते। जनभागीदारी समिति के माध्यम से प्राप्त सहयोग भी कई स्थानों पर अपर्याप्त सिद्ध होता है, विशेषकर उन महाविद्यालयों में जहाँ स्थानीय समाज की आर्थिक स्थिति सीमित है। जनभागीदारी समिति की निष्क्रियता भी एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में सामने आती है। कुछ महाविद्यालयों में समिति केवल औपचारिक रूप से अस्तित्व में रहती है और उसके द्वारा ग्रंथालय विकास के लिए ठोस प्रयास नहीं किए जाते। समिति की बैठकों का नियमित आयोजन न होना, सदस्यों की सीमित रुचि तथा स्पष्ट योजना का अभाव ग्रंथालय विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में समिति अपनी अपेक्षित भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाती।

प्रशासनिक जटिलताएँ भी ग्रंथालय विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं की जटिलता, स्वीकृति में विलंब तथा उत्तरदायित्व की अस्पष्टता के कारण विकास संबंधी कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो पाते। कई बार जनभागीदारी समिति और महाविद्यालय प्रशासन के बीच समन्वय की कमी भी देखने को मिलती है, जिससे ग्रंथालय से संबंधित योजनाएँ प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं हो पातीं। मानव संसाधनों की कमी भी ग्रंथालयों की एक प्रमुख समस्या है। अनेक महाविद्यालयों में प्रशिक्षित पुस्तकालयकर्मियों का अभाव है। सीमित स्टाफ के कारण ग्रंथालय सेवाओं का विस्तार कठिन हो जाता है और उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता। पुस्तकालयकर्मियों पर अतिरिक्त कार्यभार होने से ग्रंथालय के विकास पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा पाता।

ग्रंथालयों के प्रति जागरूकता का अभाव भी एक गंभीर चुनौती है। कई स्थानों पर महाविद्यालय प्रशासन, जनभागीदारी समिति तथा समाज के सदस्यों में ग्रंथालय के महत्व के प्रति पर्याप्त समझ नहीं पाई जाती। ग्रंथालय को केवल पुस्तकों के भंडार के रूप में देखा जाता है और उसके शैक्षणिक महत्व को अपेक्षित महत्व नहीं दिया जाता। इस मानसिकता के कारण ग्रंथालय विकास को प्राथमिकता नहीं मिल पाती। भौगोलिक एवं क्षेत्रीय असमानताएँ भी ग्रंथालय विकास को प्रभावित करती हैं। इंदौर संभाग के शहरी क्षेत्रों के महाविद्यालयों में अपेक्षाकृत अधिक संसाधन उपलब्ध होते हैं, जबकि ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के महाविद्यालय संसाधनों की कमी से अधिक प्रभावित रहते हैं। जनभागीदारी समिति का प्रभाव भी इन क्षेत्रों में सीमित रहता है, जिससे ग्रंथालय विकास की गति असमान हो जाती है।

इन समस्याओं एवं चुनौतियों के कारण महाविद्यालयीन ग्रंथालयों का विकास अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच सका है। यद्यपि जनभागीदारी समिति ने कुछ हद तक इन कठिनाइयों को कम करने का प्रयास किया है, फिर भी ग्रंथालयों के समग्र विकास के लिए इन समस्याओं का समाधान आवश्यक है। इन चुनौतियों का सम्यक् विवेचन ग्रंथालय विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक आवश्यक आधार प्रदान करता है, जिससे भविष्य में अधिक प्रभावी और संतुलित प्रयास किए जा सकें।

सुधार की संभावनाएँ एवं सुझाव : इंदौर संभाग के महाविद्यालयीन ग्रंथालयों के विकास से संबंधित समस्याओं एवं चुनौतियों के विवेचन के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि यदि उपयुक्त दिशा एवं संगठित प्रयास किए जाएँ, तो ग्रंथालयों की स्थिति में अपेक्षित सुधार संभव है। जनभागीदारी समिति इस दिशा में एक महत्वपूर्ण माध्यम सिद्ध हो सकती है, बशर्ते उसे अधिक सक्रिय, उत्तरदायी एवं उद्देश्यपरक बनाया जाए। निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से महाविद्यालयीन ग्रंथालयों के विकास हेतु सुधार की संभावनाओं को रेखांकित किया जा सकता है।

सबसे पहले यह आवश्यक है कि जनभागीदारी समिति को ग्रंथालय विकास के प्रति अधिक जागरूक और संवेदनशील बनाया जाए। समिति के सदस्यों को यह स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि ग्रंथालय केवल पुस्तकों का भंडार नहीं है, बल्कि यह महाविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता का मूल आधार है। इस दृष्टिकोण के विकास से समिति ग्रंथालय को प्राथमिकता देते हुए उसके विकास के लिए ठोस पहल कर सकती है। ग्रंथालयों की आधारभूत संरचना के सुदृढीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जहाँ ग्रंथालय भवन अपर्याप्त हैं, वहाँ उनके विस्तार अथवा पृथक भवन की व्यवस्था की जानी चाहिए। वाचनालय की क्षमता बढ़ाने, बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा प्रकाश एवं वायु की अनुकूल व्यवस्था के लिए जनभागीदारी समिति के सहयोग से योजनाएँ बनाई जा सकती हैं। इससे ग्रंथालय का उपयोग बढ़ेगा और विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त होगा।

संसाधन विकास की प्रक्रिया को भी अधिक व्यवस्थित बनाने की आवश्यकता है। पुस्तकों, संदर्भ ग्रंथों एवं पत्रिकाओं के चयन में शिक्षकों एवं पुस्तकालयकर्मियों की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि ग्रंथालय की सामग्री पाठ्यक्रम एवं विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। जनभागीदारी समिति स्थानीय दानदाताओं एवं समाजसेवियों के माध्यम से ग्रंथालय के लिए उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराने में सहायक भूमिका निभा सकती है।

मानव संसाधनों के सुदृढीकरण की दिशा में भी प्रयास आवश्यक हैं। प्रशिक्षित पुस्तकालयकर्मियों की नियुक्ति एवं उनके लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था ग्रंथालय सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ा सकती है। जनभागीदारी समिति इस दिशा में प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर सहयोग प्रदान कर सकती है। ग्रंथालयों के प्रति समाज एवं विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है। पुस्तक प्रदर्शनी, वाचन कार्यक्रम, परिचर्चा एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से ग्रंथालय को एक सक्रिय शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। जनभागीदारी समिति इन गतिविधियों के आयोजन में मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान कर सकती है।

अंततः यह आवश्यक है कि जनभागीदारी समिति और महाविद्यालय प्रशासन के बीच समन्वय एवं संवाद को सुदृढ बनाया जाए। स्पष्ट दायित्व निर्धारण, नियमित बैठकें तथा योजनाबद्ध कार्यप्रणाली ग्रंथालय विकास की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकती हैं। यदि इन सुधारतात्मक उपायों को गंभीरता से अपनाया जाए, तो इंदौर संभाग के महाविद्यालयीन ग्रंथालयों के आधारभूत ढाँचे एवं संसाधनों का सतत एवं समग्र विकास संभव है। इस प्रकार, सुधार की ये संभावनाएँ न केवल ग्रंथालयों की वर्तमान समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त करती हैं, बल्कि भविष्य में उन्हें एक सशक्त शैक्षणिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा भी प्रदान करती हैं।

III. उपसंहार

इंदौर संभाग के महाविद्यालयीन ग्रंथालयों के आधारभूत ढाँचे एवं संसाधन विकास के संदर्भ में जनभागीदारी समिति की भूमिका का समग्र विवेचन यह स्पष्ट करता है कि ग्रंथालय उच्च शिक्षा संस्थानों का एक अनिवार्य और केंद्रीय अंग है। ग्रंथालय के बिना न तो शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है और न ही विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास अपेक्षित स्तर तक पहुँच सकता है। इस दृष्टि से महाविद्यालयीन ग्रंथालयों का सुदृढीकरण उच्च शिक्षा की गुणवत्ता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ विषय है। अनेक महाविद्यालयीन ग्रंथालय आज भी आधारभूत सुविधाओं एवं संसाधनों की कमी से ग्रस्त हैं। सीमित शासकीय सहायता, प्रशासनिक जटिलताएँ तथा संसाधनों की बढ़ती आवश्यकता के कारण ग्रंथालयों का विकास अपेक्षित गति से नहीं हो पाया है। ऐसी परिस्थितियों में जनभागीदारी समिति की भूमिका एक सहायक एवं पूरक व्यवस्था के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। समिति के माध्यम से स्थानीय समाज की सहभागिता सुनिश्चित कर ग्रंथालयों के विकास को नई दिशा प्रदान की जा सकती है।

इंदौर संभाग के संदर्भ में यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जहाँ जनभागीदारी समिति सक्रिय, संगठित एवं उद्देश्यपरक रही है, वहाँ महाविद्यालयीन ग्रंथालयों की स्थिति अपेक्षाकृत सुदृढ हुई है। भवन विस्तार, वाचनालय सुविधाओं का विकास, फर्नीचर की व्यवस्था तथा पुस्तकों एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री का संवर्धन समिति के सहयोग से संभव हो पाया है। इसके विपरीत, जहाँ समिति औपचारिकता तक सीमित रही है, वहाँ ग्रंथालय विकास की प्रक्रिया धीमी एवं असंतोषजनक रही है।

इस विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जनभागीदारी समिति केवल वित्तीय सहयोग का माध्यम नहीं है, बल्कि यह ग्रंथालयों के विकास के लिए सामाजिक चेतना एवं उत्तरदायित्व की भावना को भी सुदृढ करती है। समिति के माध्यम से ग्रंथालय को महाविद्यालय और समाज के साझा संसाधन के रूप में विकसित किया जा सकता है। इससे न केवल शैक्षणिक वातावरण समृद्ध होता है, बल्कि समाज में ज्ञान के महत्व के प्रति भी सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। अतः इंदौर संभाग के महाविद्यालयीन ग्रंथालयों के आधारभूत ढाँचे एवं संसाधन विकास के लिए जनभागीदारी समिति की भूमिका को और अधिक सशक्त, सक्रिय एवं उद्देश्यपरक बनाए जाने की आवश्यकता है। यदि समिति और महाविद्यालय प्रशासन के मध्य समन्वय को सुदृढ किया जाए तथा ग्रंथालय विकास को प्राथमिकता प्रदान की जाए, तो महाविद्यालयीन ग्रंथालयों का सतत एवं समग्र विकास संभव है। यह विकास न केवल उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के बौद्धिक निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा।

संदर्भ सूची

1. रंगनाथन, एस. आर. (1931). फाइव लॉज़ ऑफ़ लाइब्रेरी साइंस. मद्रास: मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन।
2. रंगनाथन, एस. आर. (1957). लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन. बंबई: एशिया पब्लिशिंग हाउस।
3. रंगनाथन, एस. आर. (1967). प्रोलगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन. बंबई: एशिया पब्लिशिंग हाउस।
4. कृष्ण कुमार. (1987). लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट. नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग हाउस।

5. कौला, पी. एन. (1992). लाइब्रेरी एंड सोसाइटी. नई दिल्ली: एस. चंद एंड कंपनी।
6. करिसिद्धप्पा, सी. आर. (2004). कलेक्शन डेवलपमेंट इन लाइब्रेरीज़. नई दिल्ली: एसोसिएटेड पब्लिशर्स।
7. राव, एस. के. (1998). प्रॉब्लम्स ऑफ़ कॉलेज लाइब्रेरीज़ इन इंडिया. इंडियन लाइब्रेरी जर्नल, 23(2), 45-52।
8. अग्रवाल, एस. पी. (2001). अकादमिक लाइब्रेरीज़ इन इंडिया. नई दिल्ली: अटलांटिक पब्लिशर्स।
9. सिंह, आर. आर. (2005). हायर एजुकेशन एंड लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन इंडिया. जयपुर: रावत पब्लिकेशन्स।
10. शुक्ला, डी. के. (2006). कॉलेज लाइब्रेरी सिस्टम इन इंडिया. इलाहाबाद: किताब महल।
11. वर्मा, आर. सी. (2007). ग्रंथालय संगठन एवं प्रशासन. आगरा: शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी।
12. शर्मा, आर. के. (2008). रोल ऑफ़ जनभागीदारी समिति इन हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूशन्स ऑफ़ मध्यप्रदेश. जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, 12(1), 66-74।
13. मिश्रा, एस. एन. (2009). ग्रंथालय प्रबंधन: सिद्धांत एवं व्यवहार. नई दिल्ली: रावत पब्लिकेशन्स।
14. तिवारी, पी. के. (2010). महाविद्यालयीन ग्रंथालय: संरचना एवं सेवाएँ. भोपाल: मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी।
15. यूजीसी. (2011). यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरीज़ इन इंडिया. नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।
16. मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग. (1999). जनभागीदारी योजना मार्गदर्शिका. भोपाल: शासकीय मुद्रणालय।
17. मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग. (2005). महाविद्यालयीन विकास एवं जनभागीदारी. भोपाल: शासकीय प्रकाशन।
18. कुमार, ए. (2012). ग्रंथालय एवं सूचना सेवाएँ. नई दिल्ली: के. बी. पब्लिकेशन्स।
19. पांडेय, बी. एन. (2013). भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली. इलाहाबाद: सेंट्रल बुक डिपो।
20. जोशी, एम. के. (2014). ग्रंथालय संसाधन विकास. जयपुर: रावत पब्लिकेशन्स।
21. सक्सेना, आर. एस. (2016). शैक्षणिक संस्थानों में सामुदायिक सहभागिता. नई दिल्ली: अटलांटिक पब्लिशर्स।
22. यादव, एल. एन. (2018). महाविद्यालयीन शिक्षा एवं ग्रंथालय विकास. भोपाल: मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी।



International Journal of Advanced Research in Education and Technology (IJARETY)